https://farid.ps/articles/sabra_and_shatila_massacre/hi.html

सबरा और शातिला नरसंहार

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में, फिलिस्तीन में यहूदी उपस्थिति मामूली थी: कृषि **किबुट्ज़िम** का एक बिखराव, कुछ शहरी समुदाय, और हिब्रू का पुनरुद्धार जो मुख्य रूप से पूजा और विद्वता तक सीमित था। परिदृश्य 1933 के **हावारा (ट्रांसफर) समझौते** और 1938 के **एवियन सम्मेलन** के साथ बदलना शुरू हुआ, जिन्होंने दोनों ने – बहुत अलग-अलग तरीकों से – नाजी-नियंत्रित यूरोप से यहूदी प्रवासन को सुगम बनाया। कुछ वर्षों के भीतर, प्रवासन ने फिलिस्तीन में यहूदी आबादी को कई गुना बढ़ा दिया, जिससे भूमि की जनसांख्यिकीय संतुलन और राजनीतिक क्षितिज में परिवर्तन आया।

1917 का बाल्फोर घोषणापत्र, जो बाद में **ब्रिटिश मैंडेट** की शर्तों में शामिल किया गया, ने "फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना" का समर्थन करने का वादा किया, जबकि – महत्वपूर्ण रूप से – यह निर्दिष्ट किया कि "कुछ भी न किया जाए जो मौजूदा गैर-यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों को पूर्वाग्रहित कर सकता है।" फिर भी, सियोनिस्ट आंदोलन के प्रारंभिक दिनों से ही, इसके नेतृत्व ने **विजय** और **उपनिवेशीकरण** को राज्यत्व की ओर आवश्यक चरणों के रूप में वर्णित किया। थियोडोर हर्ज़ल, चाइम वीज़मैन और बाद में डेविड बेन-गुरियन जैसे विचारकों ने फिलिस्तीन में एक यहूदी राजव्यवस्था के अस्तित्व पर बहस नहीं की, बल्कि पहले से ही बसे हुए एक भूमि में इसे सुरक्षित और विस्तारित करने पर विचार किया।

मूल निवासी आबादी के लिए – मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों समान रूप से – औपनिवेशिक मैंडेट के तहत बड़े पैमाने पर प्रवासन की संभावना ने चिंता और प्रतिरोध दोनों को जन्म दिया। 1930 के दशक के अंत की अरब विद्रोहों ने इस डर को प्रतिबिंबित किया कि यूरोपीय उत्पीड़न से शरण के रूप में प्रस्तुत क्या हो रहा था, वह व्यवहार में विस्थापन का साधन बन रहा था। जो ओटोमन शासन के तहत समानांतर समुदायों के रूप में शुरू हुआ था, वह ब्रिटिश पर्यवेक्षण के तहत प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रीय परियोजनाओं में पुनर्निर्मित हो रहा था।

नकबा

नवंबर 1947 में, **संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना (रेज़ोल्यूशन 181)** ने भूमि को दो राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा, **फिलिस्तीन का 56 प्रतिशत** उस यहूदी आबादी को सौंपते हुए जो उस समय निवासियों का लगभग एक-तिहाई थी और लगभग **7 प्रतिशत भूमि** का मालिक थी। फिलिस्तीनी अरब बहुमत के लिए, यह कम से कम समझौता लग रहा था बल्कि अंतरराष्ट्रीय डिक्री द्वारा अनुमोदित विस्थापन लग रहा था। जब समुदायों के बीच गृहयुद्ध भड़का और ब्रिटिश पीछे हटे, तो सियोनिस्ट बलों ने उन्हें आवंटित क्षेत्र को तेजी से सुरक्षित और विस्तारित किया।

1948 तक, घटनाएँ स्मरण से परे तेज हो गईं। सियोनिस्ट पैरामिलिट्री – विशेष रूप से **इर्गुन** और **लही** – द्वारा अरब समुदायों और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ छेड़ा गया सशस्त्र संघर्ष खुले विद्रोह में बदल गया। उनके बम विस्फोट और हत्याएँ फिलिस्तीन से बहुत आगे फैलीं; एक हमला तो **रोम में ब्रिटिश दूतावास** को भी निशाना बनाया। थके हुए और हिंसा को नियंत्रित करने में असमर्थ होकर, **ब्रिटेन ने अपना मैंडेट त्याग दिया**, फिलिस्तीन के असाध्य प्रश्न को नवगठित **संयुक्त राष्ट्र** को सौंपते हुए।

परिणाम **नकबा** था – "विपदा" –, जिसमें **700,000 से अधिक फिलिस्तीनियों** को उनके घरों से निष्कासित या भागने के लिए मजबूर किया गया, व्यवस्थित धमकी और विनाश अभियानों के बीच। गाँव रौंद दिए गए, परिवार पड़ोसी अरब राज्यों में बिखर गए, और एक राष्ट्रीय समाज को लगभग रातोंरात विघटित कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र ने **रेज़ोल्यूशन 194** (दिसंबर 1948) के माध्यम से उनकी दुर्दशा को मान्यता दी, शरणार्थियों के वापसी या मुआवजे के अधिकार की पुष्टि करते हुए। फिर भी, वह वादा कभी लागू नहीं किया गया। इसकी गैर-कार्यान्वयन ने इज़राइल को अपनी नई सीमाओं को मजबूत करने की अनुमति दी और अरब मेजबान देशों को शरणार्थियों की उपस्थिति को **अस्थायी** मानने की अनुमति दी – एक अस्थायी स्थिति जो सात दशकों से अधिक समय से चली आ रही है।

फिलिस्तीनी डायस्पोरा

1948 की हिंसा ने विनाश और निर्वासन का परिदृश्य छोड़ दिया। **10,000 से 15,000 फिलिस्तीनियों** को लड़ाई के दौरान मारा गया जबकि हजारों अन्य को शहरों और गाँवों के गिरने पर नरसंहारों और निष्कासन में घायल किया गया। समकालीन अनुसंधान, जिसमें इतिहासकार **वालिद खालिदी** की **ऑल दैट रिमेन्स** में सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण शामिल है, **400 से अधिक फिलिस्तीनी गाँवों** के विनाश को दर्ज करता है, जिनमें से कुछ को पूरी तरह से मानचित्र से मिटा दिया गया, उनकी खंडहरों को बाद में नई इज़राइल बस्तियों या यहूदी राष्ट्रीय कोष द्वारा लगाए गए जंगलों द्वारा ढक दिया गया ताकि बस्ती के निशान छिपाए जा सकें।

1949 के ग्रीष्म तक, **शरणार्थी आबादी लगभग 750,000** तक पहुँच गई, जो युद्ध पूर्व 1.2 मिलियन अरब आबादी से थी। परिवार लहरों में भागे: पहले तटीय शहरों जैसे जाफा, हाइफा और अक्रे से; फिर गलीली और मध्य उच्चभूमि से जब सियोनिस्ट मिलिशिया – जल्द ही **इज़राइल डिफेंस फोर्सेस (IDF)** में एकीकृत – **प्लान डालेट** के तहत आगे बढ़ीं, एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट जो शत्रुतापूर्ण या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के डिपोपुलेशन को अधिकृत करता था।

पड़ोसी देशों ने मानवीय लहर को असमान रूप से अवशोषित किया।

- **जॉर्डन** ने सबसे बड़ा हिस्सा लिया, लगभग **350,000**, जिनमें से कई ने बाद में जॉर्डनियन नागरिकता प्राप्त की।
- **गाज़ा**, मिस्री प्रशासन के तहत, ने लगभग **200,000** लिया, जिससे इसकी संकरी पट्टी पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक बन गई।
- **लेबनान** ने लगभग **100,000–120,000** लिया, जिन्हें टायर, सिदोन और बेरूत के आसपास जल्दबाज़ी में बनाए गए शिविरों में रखा गया।
- **सीरिया** ने **80,000–90,000** स्वीकार किया, उन्हें दमिश्क और अलेप्पो के आसपास पुनर्वासित करते हुए। छोटी संख्या **इराक** और **मिस्र उचित** तक पहुँची, हालांकि ये शरणार्थी अक्सर स्थिरता और काम की खोज में फिर से चले गए।

संयुक्त राष्ट्र ने 1949 में **यूएनआरडब्ल्यूए (UNRWA)** – फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए राहत और कार्य एजेंसी – की स्थापना की ताकि भोजन, आश्रय और शिक्षा प्रदान की जा सके। फिर भी, एजेंसी का मैंडेट – पुनर्वास की प्रतीक्षा में अस्थायी मानवीय उपाय के रूप में अभिप्रेत – एक स्थायी लिम्बो का कंकाल बन गया। जबकि **रेज़ोल्यूशन 194** ने शरणार्थियों के वापसी के अधिकार को मान्यता दी, न तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय और न ही नया इज़राइल राज्य ने इसे लागू करने के कदम उठाए। अरब मेजबान राज्य, उसी रेज़ोल्यूशन का हवाला देते हुए, नागरिकता प्रदान करने से इनकार कर दिया, दावा करते हुए कि ऐसा करना इज़राइल के विस्थापितों को पुनर्वासित करने से इनकार को वैधता प्रदान करेगा। इस प्रकार, प्रारंभ से ही, 1948 के शरणार्थी दो नकारों के बीच फंस गए: वापसी का इनकार और संबंध का इनकार।

लेबनान में फिलिस्तीनी शरणार्थी

लेबनान, फिलिस्तीन का सबसे छोटा पड़ोसी राज्य, अपनी आकार और नाजुक सामाजिक संरचना के सापेक्ष एक असंतुलित बोझ उठा रहा था। जब 1948 में शरणार्थियों की पहली लहरें इसकी दक्षिणी सीमा पार कीं, तो वे थके हुए पहुँचे, अक्सर पैदल या गधों पर, केवल अपने घरों की चाबियाँ और खोई हुई संपत्ति के दस्तावेज़ लेकर। 1948 से 1949 के बीच, लगभग **100,000 से 120,000 फिलिस्तीनी** लेबनान में प्रवेश किए – युद्ध द्वारा निर्मित कुल शरणार्थी आबादी का लगभग एक-छठा। नवगठित **यूएनआरडब्ल्यूए (UNRWA)** ने 1952 तक उनके **127,000** को पंजीकृत किया, परिवारों को टायर, सिदोन, त्रिपोली और बेरूत के बाहरी इलाकों के पास अस्थायी शिविरों में बसाते हुए।

लेबनान का स्वागत उसके अपने **सांप्रदायिक संतुलन** से आकार लिया गया था – मरोनाइट ईसाइयों, सुन्नी और शिया मुसलमानों, और द्रूज़ों के बीच शक्ति का नाजुक विभाजन – और मुख्य रूप से सुन्नी शरणार्थियों के दसियों हज़ारों को नागरिकता प्रदान करने के डर से जो इस संतुलन को बिगाड़ सकता था। जॉर्डन के विपरीत, जिसने बाद में कई फिलिस्तीनियों को प्राकृतिक बनाया, लेबनान ने उन्हें **राज्यविहीन** रखा, निवास प्रदान किया लेकिन राष्ट्रीयता नहीं। उन्हें **मेहमान** कहा गया, एक शब्द जो अस्थायी सुरक्षा और राजनीतिक बहिष्कार दोनों का अर्थ रखता था।

प्रारंभ में, शरणार्थी कीचड़ भरे प्लॉटों पर लगाए गए तंबुओं में रहते थे, यूएनआरडब्ल्यूए राशनों और आपातकालीन सहायता पर निर्भर। समय के साथ, तंबू जिंक-छत वाले झोपड़ियों में बदल गए और बाद में कंक्रीट झोपड़ियों में, लेकिन उनकी **कानूनी अस्थायित्व** कोडिफाइड रहा। कानून द्वारा, फिलिस्तीनियों को संपत्ति का मालिक होना, ट्रेड यूनियनों में शामिल होना या सत्तर से अधिक पेशों में काम करना प्रतिबंधित था, जिसमें चिकित्सा, कानून और इंजीनियरिंग शामिल थे। शिविरों और शहरों के बीच आवागमन के लिए परमिट की आवश्यकता थी; शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच हमेशा कम वित्त पोषित यूएनआरडब्ल्यूए प्रणाली पर निर्भर थी।

बारह आधिकारिक शिविर अंततः आकार लेने लगे, सिदोन के पास **ऐन अल-हिल्वेह** से – अब लेबनान का सबसे बड़ा – बेरूत में **शातिला** और **बुर्ज अल-बराजनेह** तक। भीड़भाड़ जल्द ही चौंकाने वाली घनत्व तक पहुँच गई: शातिला में, **30,000 लोग आधे वर्ग किलोमीटर से कम में रहते थे**। बुनियादी ढाँचा न्यूनतम था; सीवेज और जल प्रणालियाँ सड़ रही थीं; बिजली दिन में कुछ घंटों के लिए झिलमिलाती थी। फिर भी, वंचना के बीच, शिविर लचीलापन के स्थान भी बन गए – स्कूलों, क्लिनिकों और राजनीतिक संगठनों के साथ जो **वापसी के अधिकार** में लंगर डाली गई सामूहिक पहचान को बनाए रखते थे।

लेबनानी अधिकारी, राजनीतिक प्रतिष्ठान के अधिकांश द्वारा समर्थित, दृढ़ता से जोर देते थे कि फिलिस्तीनियों की उपस्थिति अस्थायी थी। यह दृढ़ता केवल जनसांख्यिकीय नहीं बल्कि वैचारिक थी: तर्क दिया गया कि शरणार्थियों को एकीकृत करना ही वह दावा भंग कर देगा कि उन्हें एक दिन अपनी मातृभूमि लौटना होगा। परिणामस्वरूप, **लेबनान में फिलिस्तीनी निर्वासन एक मानवीय स्थिति और एक राजनीतिक बयान दोनों बन गया** – एक दृश्य साक्ष्य एक घाव का, जिसे अरब दुनिया ने समय से पहले ठीक न करने की कसम खाई थी।

वापसी का अधिकार

दशकों तक शिविर न केवल निर्वासन की भूगोल थे बल्कि धीरे-धीरे सुलगती नैतिक आपातकाल थे। कल्पना कीजिए पीढ़ियों को तंबू वाली गलियों में जन्म लेते हुए जहाँ आपके दादा-दादी का घर केवल एक तकिए के नीचे रखी चाबी की स्मृति में मौजूद है – जहाँ आपको बार-बार और आधिकारिक रूप से कहा जाता है कि आप कभी भी संबंधित नहीं होंगे। तीस वर्षों से अधिक समय के बाद, जब **वापसी का अधिकार** एक कागजी वादा बना रहा, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव गूंजे लेकिन लागू नहीं किए गए, और मेजबान राज्य विस्थापन को अस्थायी प्रशासनिक समस्या मानते थे, लेबनान के कई फिलिस्तीनियों ने एक उदास अंकगणित का सामना किया: कोई नागरिकता नहीं, सीमित काम, सीमित शिक्षा, और भूमि या गरिमा वापस पाने का कोई कानूनी मार्ग नहीं। गरीबी केवल भौतिक नहीं थी; वह विधिक थी: एक स्थिति जो स्थायित्व को असंभव बनाने वाले कानूनों और नीतियों द्वारा उत्पन्न और मजबूत की गई।

ऐसी स्थिति के कट्टरपंथीकरण को देखना कठिन नहीं है। जब कूटनीतिक उपचार रुक जाते हैं और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ प्रवर्तन प्रदान करने में विफल रहती हैं, तो साधारण लोग अक्सर अपने पहुँच में उपलब्ध उपकरणों की ओर पहुँचते हैं – पहले संगठित राजनीति, और फिर कुछ के लिए सशस्त्र प्रतिरोध। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) और उसके घटक गुरिल्ला समूहों का उदय उस विस्थापन की पृष्ठभूमि के खिलाफ पढ़ा जाना चाहिए। कई शरणार्थियों के लिए, हथियार उठाना एक अमूर्त विचारधारा नहीं था बल्कि दैनिक अपमान के लिए एक ठोस प्रतिक्रिया थी: मूल नागरिक और आर्थिक अधिकारों का इनकार, सीमाओं का सील करना, और घर का धीमा विलोपन। 1948 में गाँवों को रौंदते और पड़ोसियों को निष्कासित होते देखने वाली आबादी के लिए, और फिर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को उनके अधिकारों को मान्यता देते लेकिन लागू न करने को देखते हुए, हिंसा एकमात्र भाषा लगने लगी जो ध्यान, लाभांश और – कितना ही दुखद हो – सुरक्षा उत्पन्न करने में सक्षम थी।

यह मानवीय तर्क समझाता है कि सशस्त्र गुटों ने शिविरों और उनके आसपास आधार स्थापित क्यों किए, उन्होंने वहाँ सामाजिक सेवाएँ क्यों संगठित कीं, और शिविर समय के साथ सैन्यीकृत क्यों हो गए। यह बाद के नुकसानों को उचित नहीं ठहराता। इज़राइली सीमा पार गुरिल्ला संचालन ने प्रतिशोध आमंत्रित किए जो मुख्य रूप से नागरिकों पर गिरे; सामूहिक दंडों ने लेबनानी भयों को गहरा किया और कठोर उपायों के लिए पूर्वाग्रह प्रदान किए। संक्षेप में, बल का उपयोग एक फीडबैक लूप बन गया: राज्यविहीनता और हाशिएकरण ने शरणार्थी आबादी के हिस्सों को उग्रवाद की ओर धकेला; उग्रवाद ने सैन्य प्रतिक्रियाएँ और राजनीतिक अवैधकरण आमंत्रित किया; उन प्रतिक्रियाओं ने शरणार्थियों के बहिष्कार को मजबूत किया।

इस दृष्टिकोण से, 1982 का आक्रमण – और सबरा और शातिला में होने वाला नरसंहार – कोई सहज विघटन नहीं था बल्कि विफल अधिकारों, कटे हुए उपचारों और बढ़ते प्रतिशोध चक्रों से गढ़ी गई श्रृंखला का विनाशकारी अंतिम बिंदु था। नैतिक

जटिलता स्पष्ट है: शिविरों के लिम्बो को उत्पन्न करने वाला राज्य और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली उन स्थितियों को बनाने के लिए जिम्मेदार है जिनमें लोग प्रतिरोध करने के लिए मजबूर महसूस करते थे – लेकिन जो प्रतिरोध हिंसक रूप लेता है, विशेष रूप से जब नागरिकों को निशाना बनाता है, तो नए पीड़ितों को भी उत्पन्न करता है और नैतिक गर्त को चौड़ा करता है।

प्रतिरोध का अधिकार

अंतरराष्ट्रीय कानून स्वयं उन विकल्पों के बाद के औचित्य के लिए कुछ आधार प्रदान करता है। **चौथी जिनेवा संधि** और **1977 के अतिरिक्त प्रोटोकॉल I** के तहत, **विदेशी कब्जे** के तहत रहने वाली आबादी को उस कब्जे का प्रतिरोध करने का अधिकार है – जिसमें कुछ परिस्थितियों में सशस्त्र साधनों द्वारा भी – जब तक कि ऐसा प्रतिरोध नागरिकों को निशाना बनाने के निषेधों का सम्मान करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1960 और 1970 के दशक में बार-बार इस सिद्धांत की पुष्टि की, रेज़ोल्यूशनों में "औपनिवेशिक और विदेशी प्रभुत्व के तहत लोगों के संघर्ष की वैधता को स्व-निर्धारण के अधिकार का प्रयोग करने के लिए" मान्यता देते हुए।

क्या ये प्रावधान उन फिलिस्तीनियों पर लागू होते हैं जो **निर्वासन में रहते हैं** न कि सीधे कब्जे के तहत, बहस का विषय है। उनकी भूमि और घर इज़राइल राज्य के नियंत्रण में बने रहे, फिर भी वे स्वयं पड़ोसी क्षेत्रों में कैद थे, वापसी से वंचित और प्रभावी रूप से राज्यविहीन। कई फिलिस्तीनी विचारकों और न्यायविदों के लिए, वह निर्वासन प्रतिरोध के अधिकार को रद्द नहीं करता; यह केवल युद्धक्षेत्र को विस्थापित करता है। उनके दृष्टिकोण से, सशस्त्र प्रतिरोध का अधिकार एक ऐसे लोगों तक विस्तारित होता है जिनकी **कब्जा सीमाओं के पार उनका पीछा किया** – निष्कासन, नाकाबंदी और शरणार्थी शिविरों में ही सैन्य घुसपैठ के माध्यम से।

व्यवहार में, ये कानूनी तर्क जीती गई वास्तविकता को बदलने में कम सफल रहे: इज़राइल ने लेबनानी मिट्टी से सभी सशस्त्र गतिविधि को आक्रमण माना, जबकि लेबनान ने शरणार्थी लड़ाकों को मेहमान और दायित्व दोनों के रूप में माना। परिणाम एक राज्य के भीतर राज्य था – **दक्षिणी लेबनान में PLO की क्वासी-स्वायत्त उपस्थिति** –, जिसे कुछ गुटों ने सहन किया और अन्य ने घृणा की। जैसे-जैसे 1970 का दशक आगे बढ़ा, शिविर न केवल विस्थापन के प्रतीक बने बल्कि एक विस्तारित क्षेत्रीय संघर्ष की फ्रंटलाइनों में भी।

लेबनान में PLO

1960 के दशक के अंत तक, लेबनानी शरणार्थी शिविर निर्वासन में फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गए थे। **1967 के छह-दिवसीय युद्ध** और इज़राइल के वेस्ट बैंक और गाज़ा के कब्जे के बाद, फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूह अरब दुनिया में बिखर गए, उनकी जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में आधार ट्रांसनेशनल संघर्ष के नोड्स में बदल गए।

सितंबर 1970 में, जॉर्डनियन राजशाही ने **ब्लैक सेप्टेम्बर** नामक खूनी गृहयुद्ध के बाद PLO को निष्कासित कर दिया। हज़ारों लड़ाके उत्तरी सीमा पार लेबनान में भाग गए, जहाँ शिविरों ने शरण और तैयार भर्तियों दोनों प्रदान कीं। प्रवाह ने लेबनान के राजनीतिक संतुलन को बदल दिया। PLO ने एक समानांतर प्रशासन बनाया – अपनी **फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी** के माध्यम से स्कूलों, अस्पतालों और कल्याण प्रणालियों को चलाते हुए, जबकि **फतह**, **पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन (PFLP)** और **डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन (DFLP)** जैसे सशस्त्र विंग्स को संगठित करते हुए।

कई शरणार्थियों के लिए, PLO का आगमन सशक्तिकरण का प्रतीक था: 1948 के बाद पहली बार, फिलिस्तीनियों को केवल सहायता के प्राप्तकर्ता नहीं बल्कि अपने भाग्य के एजेंट थे। हालांकि, लेबनान के राजनीतिक प्रतिष्ठान के अधिकांश के लिए, यह एक राज्य के भीतर राज्य जैसा लग रहा था। उत्तरी इज़राइल में सीमा पार छापेमारी ने प्रतिशोधी हवाई हमलों को आमंत्रित किया जो लेबनानी नागरिकों को मारते थे और बुनियादी ढाँचे को नष्ट करते थे, उन समुदायों में नाराज़गी को गहरा करते हुए जिन्होंने युद्ध की मेजबानी चुनने का विकल्प नहीं किया था।

लेबनानी राज्य और PLO के बीच असहज सह-अस्तित्व को 1969 के **काहिरा समझौते** में औपचारिक रूप दिया गया, जिसे मिस्र ने मध्यस्थता की। इसने शिविरों में फिलिस्तीनियों को सीमित स्वायत्तता प्रदान की और इज़राइल के खिलाफ प्रतिरोध के उद्देश्य से हथियार ले जाने का अधिकार – लेबनानी संप्रभु क्षेत्र पर अभूतपूर्व रियायत। कुछ समय के लिए, यह

व्यवस्था एक नाजुक संतुलन बनाए रखी: लेबनान फिलिस्तीनी कारण के साथ एकजुटता का दावा कर सकता था जबकि शरणार्थियों के कल्याण और सुरक्षा की जिम्मेदारी को हस्तांतरित कर सकता था।

लेकिन जैसे-जैसे लेबनान के अपने संप्रदायिक तनाव बिगड़े, व्यवस्था विघटित हो गई। PLO की सैन्य शक्ति और राजनीतिक प्रभाव बढ़ा, इसे लेबनान के **1975–1990 गृहयुद्ध** में वामपंथी और मुस्लिम गुटों के साथ संरेखित करते हुए, जबकि दक्षिणपंथी ईसाई मिलिशिया, विशेष रूप से **फलांगी**, ने फिलिस्तीनियों को जनसांख्यिकीय खतरे और विदेशी सेना दोनों के रूप में देखना शुरू कर दिया। फलांगी और PLO-संबद्ध बलों के बीच टकराव बेरूत और दक्षिण में भड़क उठे, पड़ोसों और शिविरों को फ्रंटलाइनों में बदलते हुए।

सीमा के पार अराजकता का निरीक्षण करते हुए इज़राइल ने लेबनान को न केवल एक सुरक्षा खतरे बल्कि एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया। इज़राइली नेतृत्व ने PLO को सैन्य रूप से निष्प्रभावी करने का प्रयास किया जबकि ईसाई मिलिशिया के साथ गठबंधन पोषित किया जो एक सामान्य शत्रु साझा करते थे। 1970 के दशक के अंत से, इज़राइल ने **साउथ लेबनान आर्मी (SLA)** और **फलांगी आंदोलन** के तत्वों को हथियार, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिकल समर्थन प्रदान किया, अपनी उत्तरी सीमा के साथ एक प्रॉक्सी बल का प्रभावी निर्माण करते हुए।

मार्च 1978 में, इज़राइल की तटीय राजमार्ग पर PLO के हमले के बाद जो 38 नागरिकों को मार डाला, इज़राइल ने **ऑपरेशन लितानी** शुरू किया, लितानी नदी तक आक्रमण करते हुए और 1,000 से अधिक लेबनानी और फिलिस्तीनी नागरिकों को मार डालते हुए। हालांकि ऑपरेशन को आतंकवाद-विरोधी उपाय के रूप में उचित ठहराया गया, इसका अंतर्निहित लक्ष्य PLO को उत्तर की ओर धकेलना और SLA द्वारा गश्त की गई बफर ज़ोन स्थापित करना था। **यूएन इंटरिम फोर्स इन लेबनान (UNIFIL)** को प्रतिक्रिया में तैनात किया गया, लेकिन इसका मैंडेट कमजोर था और इसकी उपस्थिति मुख्य रूप से प्रतीकात्मक थी।

अगले कुछ वर्षों में वृद्धि का चक्र देखा गया: PLO छापेमारी, इज़राइली हवाई हमले, प्रतिशोधी गोलाबारी, और दोनों पक्षों का धीरे-धीरे जड़ जमाना। **1981** तक, इज़राइली अधिकारियों ने दावा किया कि सीमा पार गोलीबारी से प्रतिवर्ष 200 से अधिक इज़राइली मारे जाते हैं, जबकि लेबनानी शहरों को बदले में नियमित बमबारी का सामना करना पड़ा। उसी अवधि में, **अरियल शारोन**, तत्कालीन इज़राइल के रक्षा मंत्री, ने एक व्यापक योजना तैयार की – PLO को सैन्य रूप से कुचलना, इसे लेबनान से निष्कासित करना, और बेरूत में **बशीर गमायल**, मरोनाइट फलांगी नेता, के तहत एक मैत्रीपूर्ण ईसाई-नेतृत्व वाली सरकार स्थापित करना।

1982 का आक्रमण: ऑपरेशन पीस फॉर गलीली

6 जून 1982 को, इज़राइल ने **ऑपरेशन पीस फॉर गलीली** कोड नाम से लेबनान पर पूर्ण पैमाने का आक्रमण शुरू किया। आधिकारिक तौर पर, घोषित लक्ष्य सीमित था: फिलिस्तीनी गुरिल्ला बलों को सीमा से 40 किलोमीटर उत्तर की ओर धकेलना ताकि सीमा पार रॉकेट गोलीबारी रोकी जा सके। वास्तव में, ऑपरेशन का दायरा रक्षा मंत्री **अरियल शारोन** द्वारा बहुत अधिक महत्वाकांक्षी रूप से तैयार किया गया था और प्रधानमंत्री **मेनाचेम बेगिन** द्वारा अनुमोदित था। असंभव लक्ष्यों में **PLO की सैन्य और राजनीतिक बुनियादी ढाँचे का विनाश**, इसके नेतृत्व को लेबनान से निष्कासित करना, और बेरूत में **बशीर गमायल**, मरोनाइट फलांगी नेता, के तहत एक प्रो-इज़राइली सरकार की स्थापना शामिल थी।

आक्रमण का पैमाना इसकी वास्तविक मंशा को उजागर करता था। लगभग **60,000 इज़राइली सैनिक**, **800 टैंकों, कवचित ब्रिगेडों और हवाई दस्तों** द्वारा समर्थित, तट के साथ, मध्य उच्चभूमि के माध्यम से, और पूर्वी बेका घाटी में समन्वित प्रहारों में सीमा पार कर गए। आक्रमण ने जल्दी से UNIFIL की स्थितियों और लेबनानी गाँवों को अभिभूत कर दिया, दिनों के भीतर 40-किलोमीटर सीमा से बहुत आगे बढ़ते हुए। 8 जून तक, इज़राइली बलों ने **टायर और सिदोन** पर कब्जा कर लिया; 14 जून तक, **बेरूत** स्वयं घेराबंदी में था – लगभग एक मिलियन नागरिकों वाला शहर, अब घेराबंदी में।

मानवीय क्षति आश्चर्यजनक थी। लेबनानी सरकार के अनुमानों के अनुसार, युद्ध के प्रारंभिक चरण में **लगभग 17,000–18,000 लोग** – मुख्य रूप से नागरिक – मारे गए, और कई हज़ार अन्य घायल हुए। सिदोन और पश्चिम बेरूत के पूरे पड़ोस को निरंतर बमबारी के तहत समतल कर दिया गया। स्थानीय पत्रकारों, जिसमें **रॉबर्ट फिस्क** और **थॉमस फ्राइडमैन** शामिल हैं, ने प्रलयकारी विनाश की दृश्यों का वर्णन किया: मोमबत्ती की रोशनी पर चलने वाले अस्पताल, गलियों में ढेर लगे शव, और बच्चे पानी की तलाश में सफेद झंडे लहराते हुए।

बेरूत की घेराबंदी

जून के अंत तक, PLO के शेष लड़ाके – लगभग **11,000** – पश्चिम बेरूत में जड़ जमा चुके थे, भूमि, समुद्र और हवा से इज़राइल डिफेंस फोर्सेस (IDF) द्वारा घिरे हुए। घेराबंदी लगभग दस सप्ताह चली। इज़राइली तोपखाने और हवाई हमलों ने घनी आबादी वाले इलाकों पर दिन-रात धावा बोला, बिजली, भोजन और चिकित्सा आपूर्ति काट दी। गाज़ा अस्पताल और मकासेद जैसे अस्पताल अभिभूत हो गए। मृतकों की संख्या दैनिक बढ़ रही थी। पश्चिमी राजनयिकों ने बमबारी की तुलना स्टालिनग्राद की घेराबंदी से की, नोट करते हुए कि फंसे हुए नागरिक आबादी के खिलाफ इज़राइल की आग्नेय शक्ति "पूरी तरह से असंतुलित" थी।

अंतरराष्ट्रीय आक्रोश बढ़ा। **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** ने **रेज़ोल्यूशन 508** में आक्रमण की निंदा की, तत्काल युद्धविराम की मांग करते हुए। अमेरिकी दूत **फिलिप हबीब** ने संधि करने के लिए अथक प्रयास किया। सप्ताहों के दबाव के बाद, **अगस्त 1982** में एक समझौता हुआ:

- **PLO बेरूत को खाली कर देगी मल्टीनेशनल फोर्स (MNF)** की सुरक्षा में, जिसमें अमेरिकी, फ्रेंच और इतालवी सैनिक शामिल थे।
- इज़राइल अपनी प्रगति रोक देगा और पीछे छूटे नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी देगा।
- MNF संक्रमण की निगरानी करने और प्रतिशोध को रोकने के लिए अस्थायी रूप से रहेगी।

21 अगस्त से 1 सितंबर के बीच, लगभग **14,400 PLO लड़ाके** और उनके परिवार ट्यूनिशिया, सीरिया और अन्य अरब राज्यों के लिए बेरूत से रवाना हो गए। निकासी अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण के तहत की गई और उस समय इसे कूटनीतिक सफलता के रूप में सराहा गया – घेराबंदी का व्यवस्थित अंत जो अंततः लेबनान को स्थिर कर सकता था।

लेकिन शांति भ्रामक साबित हुई। इज़राइल ने वादा किया था बेरूत की परिधि से पीछे नहीं हटा; उसके बल शहर के आसपास तैयार रहे। **14 सितंबर** को, अंतिम PLO काफिले के बंदरगाह से रवाना होने के केवल कुछ दिनों बाद, एक विशाल विस्फोट ने पूर्व बेरूत में फलांगी मुख्यालय को फाड़ दिया, राष्ट्रपति-निर्वाचित **बशीर गमायल** को मार डालते हुए – शारोन की युद्धोत्तर राजनीतिक दृष्टि का इज़राइल का मुख्य सहयोगी और कोने का पत्थर। हत्या, जो सीरियन सोशल नेशनलिस्ट पार्टी के एक सदस्य को जिम्मेदार ठहराई गई, ने इज़राइल के योजनाओं को तोड़ दिया और लेबनान को फिर से अराजकता में डुबो दिया।

सबरा और शातिला नरसंहार

जब **15 सितंबर 1982** को इज़राइली टैंक **पश्चिम बेरूत** में प्रवेश किए, तो **सबरा** पड़ोस और सटा हुआ **शातिला शरणार्थी शिविर** उस क्षेत्र में था जिसे उन्होंने जल्दी से सील कर दिया। ये घनी आबादी वाले जिले थे, जिनमें अनुमानित **20,000–30,000 नागरिक** रहते थे, मुख्य रूप से फिलिस्तीनी शरणार्थी और गरीब लेबनानी शिया परिवार। अंतिम PLO लड़ाके शहर छोड़ चुके थे दो सप्ताह पहले। जो बचा था वह असशस्त्र नागरिक थे – पुरुष, महिलाएँ, बच्चे और वृद्ध – जो मानते थे कि वे अमेरिका और इज़राइल द्वारा गारंटीकृत युद्धविराम की सुरक्षा में हैं।

बशीर गमायल, फलांगी नेता, की हत्या ने प्रतिशोध का बहाना प्रदान किया। **16 सितंबर** की दोपहर, **रक्षा मंत्री अरियल शारोन** और **चीफ ऑफ स्टाफ राफेल ईतन** ने **फलांगी कमांडरों** से, जिसमें **एलिये होबेका** शामिल थे, बेरूत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास इज़राइल डिफेंस फोर्सेस के फॉरवर्ड कमांड पोस्ट पर मुलाकात की। फलांगी – इज़राइल के करीबी सहयोगी – को शिविरों में प्रवेश करने की अनुमति दी गई "आतंकवादी अवशेषों को उखाड़ने के लिए।" इज़राइली अधिकारियों ने लॉजिस्टिक्स का समन्वय किया, परिवहन प्रदान किया, और क्षेत्र को सैनिकों और कवचित वाहनों से घेर लिया। उन्होंने रातों में **उद्भासित फ्लेयर्स** भी दागे ताकि मिलिशिया के संचालन को सुगम बनाया जा सके।

एक बार अंदर, फलांगी इकाइयों ने अविवेकपूर्ण हत्या शुरू कर दी। अगले **चालीस घंटों** में, गुरुवार शाम से शनिवार सुबह तक, वे घर से घर गए, पूरे परिवारों को निष्पादित करते हुए, महिलाओं पर हमला करते हुए, और बॉडीज को बुलडोज़र से सामूहिक कब्रों में धकेलते हुए। कई पीड़ितों को निकट दूरी से गोली मार दी गई; अन्य चाकू या ग्रेनेड से मारे गए। उत्तरजीवी बाद में लाशों से लटकी सड़कों और हवा को भरते सड़न की दुर्गंध का वर्णन किया।

नरसंहार के दौरान, **इज़राइली सैनिकों ने शिविरों के आसपास कॉर्डन बनाए रखे**, प्रवेश और निकास बिंदुओं को नियंत्रित करते हुए। क्रूरताओं की रिपोर्टें घंटों के भीतर रेडियो द्वारा इज़राइली कमांडरों तक पहुँच गईं। **अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस** के पर्यवेक्षक और पड़ोसी जिलों के पत्रकारों ने भी IDF अधिकारियों को सामूहिक हत्याओं के बारे में चेतावनी दी। फिर भी, सेना ने हस्तक्षेप नहीं किया। हत्याएँ लगभग दो पूरे दिनों तक जारी रहीं इससे पहले कि मिलिशिया को अंततः सुबह 8:00 बजे **18 सितंबर** को अंतरराष्ट्रीय आक्रोश और प्रत्यक्ष अमेरिकी विरोध के बाद बाहर निकलने का आदेश दिया गया।

हताहत और साक्ष्य

मृतकों की संख्या विवादित बनी हुई है लेकिन किसी भी हिसाब से भयावह।

- **अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति** ने कम से कम **1,500 शवों की बरामदगी** की रिपोर्ट की, कुल मौतें संभवतः **3,000** तक पहुँच सकती हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र महासभा जांच (1982)** ने **2,750 से 3,500** मृतकों का अनुमान लगाया।
- **इज़राइली कहान कमीशन** ने **700–800** पहचाने गए पीड़ितों की पुष्टि की लेकिन स्वीकार किया कि बहुत अधिक मारे गए।

मृतकों में फिलिस्तीनी, लेबनानी शिया और कुछ सीरियन शामिल थे – व्यावहारिक रूप से सभी नागरिक।

जिम्मेदारी और साझेदारी

हालांकि नरसंहार **फलांगी मिलिशिया** द्वारा किया गया, **इज़राइली कमांड संरचना की संलिप्तता** ऑपरेशन को सक्षम करने में निर्विवाद थी। इज़राइली बलों ने:

- शिविरों में फलांगी के प्रवेश को **अधिकृत** किया।
- क्षेत्र को **घेर लिया**, नागरिकों को भागने से रोकते हुए।
- हत्यारों की सुविधा के लिए रात्रि आकाश को **उद्भासित** किया।
- सामूहिक हत्याओं की **रिपोर्टें प्राप्त** कीं और लगभग दो दिनों तक कुछ नहीं किया।

जब 18 सितंबर को पहले अंतरराष्ट्रीय पत्रकार – जिसमें **रॉबर्ट फिस्क**, **लोरेन जेनकिन्स** और **जेनेट ली स्टीवेंस** शामिल हैं – शातिला में प्रवेश किए, तो उन्होंने एक बुरे सपने का सामना किया: शवों से भरी गलियाँ, बुलडोज़र से खोदी गई गड्ढों में भरे शव, और सदमे में भटकते उत्तरजीवी। छवियों ने वैश्विक चेतना को झुलसाया और इज़राइल के दावे को तोड़ दिया कि वह "गलीली के लिए शांति" चाहता था।

जांच और वैश्विक प्रतिक्रिया

नरसंहार ने तत्काल अंतरराष्ट्रीय आक्रोश को जन्म दिया। **संयुक्त राष्ट्र महासभा** ने **रेज़ोल्यूशन 37/123** (दिसंबर 1982) में इसे "नरसंहार का कार्य" घोषित किया और इसे रोकने में विफल रहने के लिए इज़राइल को जिम्मेदार ठहराया। इज़राइल में ही, सार्वजनिक क्रोध अभूतपूर्व स्तर तक पहुँच गया: अनुमानित **400,000 लोग** – आबादी का लगभग एक-दसवाँ – **तेल अवीव** में जवाबदेही की मांग करते हुए मार्च निकाले।

सार्वजनिक दबाव के तहत, इज़राइली सरकार ने 1983 में **कहान जांच आयोग** की स्थापना की। इसके निष्कर्ष दोषपूर्ण थे, हालांकि सावधानीपूर्वक शब्दबद्ध। आयोग ने फैसला किया कि:

- इज़राइल नरसंहार के लिए **"अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी"** वहन करता है।
- **अरियल शारोन** स्पष्ट चेतावनियों के बावजूद रक्तपात को रोकने के लिए कार्रवाई न करने के लिए "व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार" था।
- अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, जिसमें **राफेल ईतन** शामिल हैं, "व्यक्तिगत दोष" वहन करते हैं।

शारोन को रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, हालांकि वह कैबिनेट में बने रहे और दो दशक बाद प्रधानमंत्री बने। कोई भी इज़राइली या फलांगी अधिकारी को कभी नरसंहार के लिए आपराधिक अभियोजन का सामना नहीं

करना पड़ा। 2001 में, उत्तरजीवियों ने शारोन और अन्य के खिलाफ **बेल्जियन युद्ध-अपराध मामले** के माध्यम से न्याय की मांग की, लेकिन मामला 2003 में क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज कर दिया गया।

मल्टीनेशनल फोर्स (MNF) – जिसका पूर्व निकासी शिविरों को असुरक्षित छोड़ गया था – सितंबर 1982 के अंत में बेरूत लौट आया, लेकिन इसकी उपस्थिति पहले से ही घटित को पूर्ववत नहीं कर सकती थी। महीनों के भीतर, नई हिंसा भड़क उठी: अमेरिकी और फ्रेंच सैनिकों के खिलाफ आत्मघाती बम विस्फोट, पश्चिमी बलों की निकासी, और लेबनान का गहरे अराजकता में वंक्षण। पश्चिम बेरूत के खंडहरों के बीच, सबरा और शातिला के उत्तरजीवियों ने अपने मृतकों को जल्दबाज़ी में खोदी गई सामूहिक कब्रों में दफनाया और शोक के लंबे, अदृश्य कार्य की शुरुआत की।

लेबनान में, सबरा और शातिला ने संप्रदायिक घावों को गहरा किया। ईसाई मिलिशिया के लिए, यह अपराधबोध और प्रतिशोध की विरासत को सीमेंट कर दिया; शिया और फिलिस्तीनी समुदायों के लिए, यह पीड़ा और अन्याय के एक संग्रहण प्रतीक बन गया। गृहयुद्ध आठ वर्षों तक चला, लगभग **150,000 मृत** छोड़ते हुए इससे पहले कि **ताइफ समझौता (1989)** अंततः एक नाजुक शांति बहाल करे। फिर भी शरणार्थी उस समझौते के राष्ट्रीय समझौते से बाहर रहे, अभी भी नागरिकता या संपत्ति अधिकारों के बिना, अभी भी उन शिविरों में कैद, जो उनके माता-पिता और दादा-दादी के घर थे।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नरसंहार ने राजनीतिक इच्छा की अनुपस्थिति में मानवीय कानून की सीमाओं को उजागर किया। **संयुक्त राष्ट्र रेज़ोल्यूशन**, **जिनेवा संधियाँ**, और **"रक्षा करने की जिम्मेदारी"** का नासेंट अवधारणा सभी ने अत्याचारों को रोकने की बाध्यताओं की घोषणा की, फिर भी कोई भी प्रभावी प्रवर्तन में अनुवादित नहीं हुई। 2000 के दशक की शुरुआत में बेल्जियन युद्ध-अपराध मामला ने जवाबदेही के प्रश्न को संक्षिप्त रूप से फिर से खोला लेकिन अंततः क्षेत्राधिकार सुधार द्वारा सीमित कर दिया गया। आज तक, किसी भी अदालत ने सबरा और शातिला में हत्याओं का फैसला नहीं किया है।

सांस्कृतिक रूप से, नरसंहार घाव और दर्पण दोनों के रूप में जीवित है। फिल्में जैसे **अरि फोलमैन की वाल्ट्ज़ विद बशीर** (2008) इज़राइली सैनिकों की साझेदारी की भटकती स्मृतियों का अन्वेषण करती हैं; साहित्यिक कार्य जैसे **इलियास खौरी की गेट ऑफ द सन** और **रॉबर्ट फिस्क की पिटी द नेशन** मानवीय विनाश को चुभती अंतरंगता के साथ दस्तावेजित करते हैं। फिलिस्तीनियों के लिए, प्रत्येक सितंबर का स्मृति दिवस कम स्मरणोत्सव है बल्कि निरंतरता का अनुष्ठान – एक याद दिलाना कि 1982 में उन्हें असुरक्षित छोड़ने वाली वही राज्यविहीनता आज लेबनानी शिविरों में और कब्जे वाले क्षेत्रों में बनी हुई है।

चालीस वर्ष बाद, **सबरा और शातिला** एक ऐतिहासिक घटना से अधिक है; यह एक नैतिक मील का पत्थर है। यह अस्वस्थ विस्थापन, अपूर्ण वादों, चुनौती न दिए गए दंडमुक्ति के परिणामों के साथ सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह दिखाता है कि जब एक पूरा लोग कानूनी संबंध से वंचित कर दिया जाता है, तो हिंसा एक अपवाद नहीं बन जाती बल्कि अपनी बारी का इंतजार कर रही अपरिहार्यता बन जाती है।

नरसंहार के उत्तरजीवी अब बूढ़े हैं, उनकी स्मृतियाँ ऐतिहासिक रिकॉर्ड में फीकी पड़ रही हैं, लेकिन उनका गवाही एक चेतावनी के रूप में जीवित है – कि राज्यविहीनों के अधिकार दुनिया के विवेक का माप हैं। अंत में, सबरा और शातिला केवल एक नरसंहार की कहानी नहीं है; यह बीसवीं शताब्दी के अपूर्ण प्रश्न की कहानी है: **न्याय को कितनी देर तक स्थगित किया जा सकता है इससे पहले कि इतिहास खुद को दोहराए?**

एपिलॉग: निर्वासन की भूगोल

नकबा और **सबरा और शातिला** अलग-अलग त्रासदियाँ नहीं हैं बल्कि एकल निरंतरता के अध्याय – शक्ति द्वारा अदृश्य बनाए गए मनुष्यों की कहानी, घोषित लेकिन लागू न किए गए कानूनों की, स्मृति की जो हथियारबद्ध की गई और फिर भूली गई। इस श्रृंखला में प्रत्येक क्षण हमें याद दिलाता है कि जब पीड़ा को मान्यता न दी जाए, तो यह नई रूपों में और नई भूमि पर पुनरुत्पादित होती है।

न्याय का वादा मुख्य रूप से बयानबाजी बना रहा। फिर भी, जो याद रखते हैं उनकी दृढ़ता – वे उत्तरजीवी जो अभी भी गायब घरों की चाबियाँ पकड़े हुए हैं, वे बच्चे जो शरणार्थी शिविरों में बड़े हो रहे हैं अभी भी वापसी का इंतजार कर रहे हैं – कुछ अटल की गवाही देते हैं: विलोपन को अंतिम फैसला बनने देने से इनकार।

यदि इस इतिहास में कोई सबक है, तो वह यह है कि विस्थापन पर निर्मित कोई सुरक्षा स्थायी नहीं हो सकती, और न्याय को बाहर करने वाली कोई शांति टिक नहीं सकती। जब तक विस्थापितों का गरिमा से जीने का अधिकार – चाहे वापसी द्वारा या मान्यता प्राप्त संबंध द्वारा – सम्मानित न किया जाए, निर्वासन की भूगोल विस्तारित होती रहेगी, और **सबरा और शातिला** के भूत हमारे साथ-साथ चलेंगे।

संदर्भ

- Al-Hout, B. N. (2004). **Sabra and Shatila: September 1982**. London: Pluto Press.
- Arens, M. (1982). Statements to the **Washington Post**, June 1982.
- Brynen, R. (2022). **Palestinian Refugees in Lebanon**. Beirut: Institute for Palestine Studies.
- Fisk, R. (1990). **Pity the Nation: Lebanon at War**. Oxford University Press.
- Folman, A. (Director). (2008). **Waltz with Bashir** [Film]. Sony Pictures Classics.
- General Assembly of the United Nations. (1947). **Resolution 181 (II): Future Government of Palestine**.
- General Assembly of the United Nations. (1948). **Resolution 194 (III): Palestine - Progress Report of the United Nations Mediator**.
- General Assembly of the United Nations. (1982). **Resolution 37/123: The Situation in the Middle East**.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). (1982). **Field Reports on the Lebanon Conflict**. Geneva.
- Israeli Government. (1983). **Report of the Commission of Inquiry into the Events at the Refugee Camps in Beirut (Kahan Commission)**. Jerusalem: State of Israel.
- Khalidi, W. (1992). **All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948**. Institute for Palestine Studies.
- Khoury, E. (2006). **Gate of the Sun**. New York: Archipelago Books.
- Peteet, J. (2005). **Landscape of Hope and Despair: Palestinian Refugee Camps**. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Security Council of the United Nations. (1982). **Resolutions 508 and 521 (1982): Ceasefire and Situation in Lebanon**.
- Shlaim, A. (2000). **The Iron Wall: Israel and the Arab World**. New York: W. W. Norton.